Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

कोविड-19:
तत्परता से जुटी योगी सरकार

सही समय पर सही निर्णय

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकजुटता का आह्वान किया. केंद्र सरकार द्वारा लिए गये नीतिगत निर्णयों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्परता के साथ अमल में लाने में सफलतापूर्वक कार्य किया है. उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिसके सामने कोरोना संकट के शुरुआती दिनों से अनेक चुनौतियां खड़ी हुईं. कोरोना पर नियंत्रण की बात हो या श्रमिकों की वापसी का विषय हो यूपी सरकार ने कठिन दौर में जनता की मदद के लिए त्वरित कदम उठाये हैं. योगी सरकार ने न सिर्फ चुनौतियों के खिलाफ कारगर कदम उठाये हैं, बल्कि भविष्य के लिहाज से ठोस उपायों पर तेजी से काम करना भी शुरू किया है.

तत्परता से उठाये कदम

- योगी सरकार द्वारा जनवरी माह में ही विश्व के अनेक देशों में कोविड-19 के शुरू हुए प्रकोप की जानकारी प्राप्त होते ही एडवाइजरी निर्गत कर आवश्यक व्यवस्था जैसे आईसोलेशन वार्ड, सुरक्षा किट, सामाजिक दूरी के सम्बंध में जागरूकता आदि हेतु आवश्यक ????? आरम्भ कर दी गईं.
- शुरुआती मामले आते ही 15 मार्च से 21 मार्च तक योगी सरकार द्वारा यातायात, बाजार, आवागमन सहित जरुरी तमाम एहतियात बरती गयी. 22 मार्च को ही उन 16 जिलों में लॉक डाउन लागू किया गया, जहां कोविड का खतरा अधिक था.
- शुरुआती स्तर पर ही सतर्कता बरतते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में "द एपिडेमिक एक्ट 1897" को लागू किया गया. इसके अन्तर्गत, अफवाहों को रोकना, रोग के लक्षण से ग्रसित किसी भी व्यक्ति को 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखना, कोविड पॉज़िटिव रोगियों के आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों को सील करने आदि की शक्तियाँ जिलाधिकारियों को प्रदान की गयीं.
- प्रत्येक जनपद में एकीकृत कन्ट्रोल रूम स्थापित कर उनके टेलीफ़ोन नम्बर जन सामान्य को उपलब्ध कराये गए .
- भारत-नेपाल सीमा के सभी चेक पोस्टों पर थर्मल एनालाइजर स्थापित किये गये. प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई. समस्त जनपदों में कोरोना से निपटने के लिए कण्ट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए.

टीम-11: कोविड से जंग में प्रोफेशनल एप्रोच

- लॉकडाउन लागू होने के तुरंत बाद 27 मार्च को जनसामान्य से लगातार संवाद करके पैदा हुई समस्याओं से निबटने हेतु कार्ययोजना बनाने के लिए अधिकारियों की देखरेख में योगी सरकार ने 'टीम-11' का गठन कर स्थिति पर निगरानी रखी. यह टीम निम्न स्थितियों पर बारीकी से नजर रखे हुए थी-
  1. निर्माण कार्य आरम्भ करने, ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था, किसानों की फसल की बुवाई, क़टाई, बिक्री, कृषि निवेश व पशुओं की देखभाल हेतु प्रबंध करने.
  2. राजस्व प्राप्तियों, रोजगार के अवसरों, उद्योगों, इकाईयों व श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने, मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को प्रारंभ करने, पेन्शन व छात्रवृत्ति वितरण.
  3. चिकित्सा व्यवस्था, शेल्टर होम की स्थापना, कम्यूनिटी किचन, दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, राशन, फल, सब्जी आदि की उपलब्धता तथा डोर स्टेप डिलीवरी.
  4. ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनेटाईजेशन व पेयजल की व्यवस्था, बुंदेलखंड एवं विन्ध्य क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता व दिव्यांगजनों के हितों की सुरक्षा.
  5. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति (होम डिलीवरी), श्रमिक, असहाय व कमजोर वर्ग के लिए घोषित सहायता पहुंचाने, आवागमन को नियन्त्रित करने, मीडिया को सही जानकारी देने, कंट्रोल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने, चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा विभागों की ईकाइयों द्वारा जनमानस को सभी सुविधाएं सुनिश्चित कराने.
  6. पशुओं के लिए चारा, भूसा बैंक आदि हेतु, आवश्यक निर्माण इकाइयों तथा दाल मिल, आटा मिल, मार्ग निर्माण इकाइयों के समन्वय हेतु, साफ़ सफाई, सैनेटाईजेशन आदि की व्यवस्था.

श्रमिकों के खातों में पहुंचाई आर्थिक सहायता

- योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा त्वरित कदम उठाते हुए 24 मार्च, 2020 को 5.97 लाख श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से को 1-1 हजार रुपए हस्तांतरित किए गए.
- योगी सरकार ने 30 मार्च, 2020 को 27.15 लाख मनरेगा श्रमिकों को देय 611 करोड़ रुपए उनके खातों में ऑनलाइन प्रक्रिया से हस्तांतरित किए.
- लगभग 1.65 करोड़ अन्त्योदय योजना, मनरेगा तथा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं दिहाड़ी मज़दूरों को 1 माह का निःशुल्क राशन अप्रैल 2020 में उपलब्ध कराने का निर्णय योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया.
- निर्माण कार्य से जुड़े 17.07 लाख चिन्हित श्रमिकों, नगरीय क्षेत्र के 8.25 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र के 6.15 लाख निराश्रित श्रमिकों को 1000 रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 31.47 लाख निराश्रित व्यक्तियों को मई के प्रथम सप्ताह तक कुल 314.71 करोड़ की राशि का वितरण किया गया.

गरीब कल्याण: मोदी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन

कोविड के खिलाफ जंग में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीतिगत दूरदर्शिता के साथ अनेक कारगर निर्णय लिए. मोदी सरकार के निर्णयों में गरीब कल्याण की भावना तथा मानवीय संवेदना के विविध पहलू स्पष्टता से उभरकर आते हैं. मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाओं को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शत-प्रतिशत अमल में लाने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. योगी सरकार ने यह सिद्ध किया है कि ऐसे कठिन दौर में केंद्र और राज्य के परस्पर समन्वय वाली 'डबल इंजन' सरकार होने का लाभ बिना रुकावट जनता को मिलता है.

- भारत सरकार द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस के माध्यम से सभी चिकित्सालयों में तैनात समस्त चिकित्सकों/ स्वास्थ्य कर्मियों को रूपये 50 लाख के बीमा से आच्छादित किया गया.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से मई तक लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों को 4747 करोड़ का भुगतान किया. 1.44 करोड़ परिवारों को मई के प्रथम सप्ताह तक कुल 167 लाख एलपीजी गैस सिलिंडर नि:शुल्क वितरित किये गये.
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्रदेश की 3.26 करोड़ महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 500 रूपये की पहली किश्त भेज दी गयी है. इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार से तीन माह में ₹4890 करोड़ धनराशि प्राप्त होगी.
- संगठित क्षेत्र के 100 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों के 3.05 लाख मज़दूरों में से 73,327 मजदूरों के पी.एफ. खातों में रू. ₹11.05 करोड़ की धनराशि भेजने का कार्य योगी सरकार ने तय समय में किया है.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अप्रैल माह के अन्त तक 3.32 करोड़ राशन कार्ड धारकों को 6.86 लाख मीट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया.
- एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत केन्द्र सरकार से ₹394.77 करोड़ की धनराशि प्राप्त कर ग्राम्य विकास विभाग को स्वयं सहायता समूहों के प्रयोजन हेतु भेजी गई है.

अशक्त को सहायता: वृद्ध, निराश्रित महिला तथा दिव्यांगजन

- 3 अप्रैल, 2020 को वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन तथा कुष्ठावस्था पेंशन के 86.72 लाख लाभार्थियों को दो माह की अग्रिम पेंशन की कुल 871.46 करोड रुपए की धनराशि ऑनलाइन भेजी गयी. विधवा पेंशनरों की दूसरी किश्त के रूप में 260 करोड़ से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है.
- ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर निकायों के असहाय व्यक्ति जिनके पास अपने व अपने परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे 8.25 लाख व्यक्तियों को जिलाधिकारी की संस्तुति पर 1,000 प्रतिमाह की दर से सहायता राशि भेजी गई.
- ठेला, रेहड़ी, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि के कामगार, पल्लेदार, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक आदि लगभग 15 लाख श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए भेजे जाने का निर्णय लिया गया.

अन्नदाता के हितों की सुरक्षा

- रबी की फ़सलों की सुगमता से कटाई सम्पन्न हुई. किसानों की माँग के अनुसार फसलों के बीज, उर्वरक आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की. कृषि उपकरणों व ट्रैक्टर आदि की उपलब्धता हेतु उनकी बिक्री केन्द्रों व सेवा केन्द्रों को खोला गया.
- 15 अप्रैल से शुरू कर 30 मई तक 5,953 सरकारी खरीद केन्द्रों पर 126.42 लाख क्विंटल गेहूँ की खरीद 4.52 लाख किसानों से की गई तथा मण्डी में कुल 63.6 लाख क्विंटल गेहूँ की ख़रीद की गयी. सरकार द्वारा दाल/तिलहन में 8571 मी.टन चना तथा 264 मी.टन सरसों की खरीद हुई.
- प्रदेश में कुल 2057 कोल्ड स्टोरेज में से 1911 कोल्ड स्टोरेज वर्तमान में चालू है. 30 मई तक कुल 156 लाख मी॰टन क्षमता के सापेक्ष 98 मी॰ टन आलू का भंडारण किया गया.
- प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान समस्त 119 चीनी मिलों का संचालन हुआ व सेनिटाइज़र उत्पादन में डिस्टिल्लरीज़ द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी.

खाद्यान्न वितरण में बरती तेजी

- प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न का निरंतर वितरण इस आपदा में किया गया. निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में मनरेगा जॉब कार्ड लाभार्थी, श्रम विभाग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूरों को भी सम्मिलित किया गया.
- माह अप्रैल, 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कुल 3.24 करोड़ कार्ड धारकों (13.45 करोड़ यूनिट) को 7.47 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया जिसमें 38 करोड़ श्रमिकों/कामगारों को निःशुल्क राशन वितरण किया गया.
- 30 मई, 2020 तक 3.57 करोड़ राशन कार्डों पर कुल 14.38 करोड़ यूनिट पर 7.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरण किया, इनमें से 95 लाख कार्ड धारकों को निःशुल्क वितरण किया गया.
- 01 मई, 2020 से उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को नेशनल राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी प्रदान की गई जिससे वे अन्य प्रदेशों में रहकर भी राशन प्राप्त कर सकें.
- फल एवं सब्जी की डिलीवरी हेतु 14,550 मोबाइल/वैन/ई-रिक्शा/ट्रैक्टर तथा 30,455 ठेला/हत्थु गाडी (मैनुअल चालित) कुल 45,005 वाहनों से फल एंव सब्जी का वितरण किया गया. कुल 20.90 करोड़ लीटर दूध का उपार्जन किया गया

आदर्श बना कम्यूनिटी किचन मॉडल

- समस्त किचन की जियो-टैगिंग कर विडियो वॉल के माध्यम से अनुश्रवण करने वाला प्रथम राज्य.
- प्रदेश के जनपदों में मई माह में कुल 3,327 कम्युनिटी किचन संचालित हैं जिनसे प्रतिदिन 12 लाख से अधिक लोगों को खाना खिलाया जा रहा है.
- मई के अंत तक प्रदेश के 400 हॉट-स्पाट क्षेत्रों में धार्मिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा 26.56 लाख एवं सामुदायिक किचन द्वारा 21.85 लाख कुल 48.42 लाख नागरिकों को भोजन कराया गया.
- स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 2.53 करोड़ एवं ज़िला प्रशासन व अन्य सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 1.95 करोड़ कुल 4.53 करोड़ नागरिकों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई.

जांच एवं उपचार की सुदृढ़ व्यवस्था

- प्रदेश सरकार द्वारा संक्रमण रोकने हेतु देश में सर्वप्रथम कोविड व नोन-कोविड अस्पताल की अलग-अलग व्यवस्था सुनिश्चित की गई.
- कोरोना संक्रमण के शुरूआती माह फरवरी, 2020 में जहाँ प्रदेश में कोविड-19 टेस्टिंग हेतु एक भी प्रयोगशाला नहीं थी, वहीं मई माह की शुरूआत में 26 प्रयोगशालाएं क्रियाशील हैं, जिनमें 22 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं.
- मई के प्रथम सप्ताह तक प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड, लगभग 26,419 क्वारंटाइन बेड उपलब्ध हैं जो सरकार के द्वारा बनाई गई ठोस रणनीति व क्रियान्वयन के फलस्वरूप ही सम्भव हुए. प्रदेश के सभी जनपदों में वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया. प्रदेश में 1466 वेंटिलेटर बेड उपलब्ध है.
- प्रदेश सरकार द्वारा 403 लेवल-1 कोविड चिकित्सालय, 75 लेवल-2 कोविड चिकित्सालय तथा 25 लेवल-3 चिकित्सालय स्थापित किए जा चुके हैं. तीनों प्रकार के अस्पतालों में 1 लाख से अधिक बेड की सुविधा का प्रबंध किया गया.
- जांच क्षमता में बढ़ोत्तरी की गयी तथा 3.6 करोड़ से अधिक लोगों का सर्वे किया गया. 2 करोड़ से अधिक लोगों ने आरोग्य एप डाउनलोड किया.

घर लौटने वाले श्रमिकों का रखा ख्याल

- मार्च, 2020 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली से आए लाखों कामगार/ श्रमिकों को दिल्ली यूपी बार्डर से प्रदेश सरकार द्वारा रातों-रात हजारों की संख्या में बसें लगाकर अपने गन्तव्य स्थल तक सकुशल पहुँचाने का कार्य किया गया.
- कोटा, राजस्थान में फंसे लगभग 12,000 से अधिक तथा प्रयागराज में 15,000 से अधिक छात्र-छात्राओं को भी निःशुल्क बस सेवा द्वारा चिकित्सीय परीक्षणोपरान्त सकुशल उनके घरों तक पहुँचाया गया.
- प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों के अपने जनपद में आगमन पर उनके चिकित्सा परीक्षण के बाद जिन कामगारों के कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाये गए उन्हें 01 माह का खाद्यान्न तथा भरण-पोषण भत्ता देकर उनके घर भेजा गया. जिन प्रवासियों में कोरोना के लक्षण पाये गये, उनका कोरोना की जाँच के बाद सक्षम स्तर के चिकित्सालय में भेजे जाने की व्यवस्था की गई.
- प्रदेश के जनपदों में कुल 18,156 आश्रय स्थल (Shelter home) स्थापित किए हैं जिनकी कुल क्षमता 14.5 लाख है तथा उनमें 1 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं.
- उ0प्र0 के श्रमिकों को अन्य प्रदेशों से लाए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष ट्रेन चलाई गई. मई तक 1567 ट्रेनों द्वारा कुल 23 लाख से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश वापस लाया गया. इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों से 14 हजार से अधिक बसों के द्वारा 3.5 लाख श्रमिक/छात्र/ अन्य व्यक्तियों को प्रदेश वापस लाया गया.

जान भी- जहान भी: सबकी चिंता की योगी सरकार ने

- उद्योगों से सम्बंधित समस्याओं का निदान करने हेतु राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम व जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई.
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन दूरभाष(1076) पर वेतन भुगतान से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया गया. प्रदेश की 84,174 औद्योगिक इकाईयों द्वारा कार्मिकों को 1682 करोड़ के वेतन का भुगतान कराया गया.
- संगठित क्षेत्र के ई.पी.एफ. के तहत 24 लाख कर्मियों के 33,560 दावों को स्वीकार कर 73.77 करोड़ की राशि भेजी गयी.
- मई के अंतिम सप्ताह तक रिकार्ड 90 लाख लीटर सेनिटाइजर का उत्पादन कर प्रदेश की आंतरिक आवश्यकता की पूर्ति करते हुए 78 लाख लीटर की आपूर्ति अन्य प्रदेशों को की गई व रोज़गार सृजन भी किया गया.

- लघु एवं मध्यम श्रेणी की 3,17,121 इकाईयों के अतिरिक्त सूक्ष्म श्रेणी की 77,830 औद्योगिक इकाइयां सक्रिय की गईं जिससे 28 लाख लोगों के रोज़गार का हित सुरक्षित हुआ.
- प्रदेश में पीपीई किट तथा मास्क निर्माण की 85 इकाइयाँ सक्रिय की गई. मेडिकल इक्यूपमेंट एवं दवा निर्माण आदि से संबंधित 412 को गति दी गयी.
- प्रदेश के ईंट भट्टों को चालू कराया गया जिससे निर्माण संबंधी जरूरत की पूर्ति हुई साथ ही भट्टों पर काम करने वाले 5 लाख से अधिक लोगों का रोज़गार बना रहा.
- निर्माण कार्य से जुड़े श्रम विभाग के पंजीकृत 16.91 लाख श्रमिकों को 'लेबर सेस फण्ड' से 1000 रूपया प्रति माह डीबीटी द्वारा उपलब्ध कराने के साथ-साथ निर्माण कार्यों को सुरक्षा प्रोटोकोल के साथ शुरू किया गया जिनमे एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी शामिल है.
- मनरेगा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से 27.15 लाख कार्ड धारकों को रू0 611 करोड़ का वितरण किया गया. मनरेगा द्वारा रोज़गार प्रदान करने में अग्रणी राज्य बना.
- 12 मई 2020 को मनरेगा अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत 35,818 रोज़गार सेवकों को 225.39 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया.
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत प्रदेश में मई तक 39 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार दिया गया तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 13,369 स्वयं सहायता समूह को कोविड-19 से निपटने के लिए सेनिटाइज़र, पी०पी०ई० व मास्क के निर्माण से जोड़कर रोज़गार प्रदान किया गया.

Published by

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-23005850

Content Source: Government of UP